(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दी फिल्मों में अश्लील और उत्तेजक दृश्यों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद ऐसे दृश्यों में तेजी से बढ़ोत्तरी होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई दण्डात्मक कानून बनाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव): (क) अश्लील और उत्तेजक दृश्यों में वृद्धि संबंधी शिकायतें/प्रेस रिपोर्टें सरकार द्वारा समय-समय पर प्राप्त की जाती हैं। इन रिपोर्टों को प्रमाणित करने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही प्रदर्शित किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम में निर्धारित दण्डों में वृद्धि करना प्रार्थित है।

Evasion of payment of import duty on marble

*31. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Importers carve a custom-made fraud in imported marble" appearing the Indian Express dated 9th June, 1995;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken to curb such frauds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Yes, Sir. The Government is aware of the news item appearing in the Indian Express dated 9th June, 1995.

(b) and (c) Import of marbel against Advance Licences under Duty Exemption Scheme were noticed in the ports of Bombay and Nhava Sheva. Goods were mostly imported against transferred Advance Licences. The imports were therefore replenishment of the imputs already used in the exports. In all cases where there was no evidence of imported marble having been used in the export products, goods were either charged to duty or allowed provisional clearance against bond under the custom, law. In cases where under-valuation was suspected, duty was charged at enhanced value provisionally. Higher export prices were in respect of articles in the nature of artifacts which are costly products of marble and therefore the allegation over invoicing is not correct. Some of the cases where controventions have been noticed were adjudicated in terms of the provisions of Customs Act and in other cases action according to law is being taken. The allegation of fraud and collusion with Customs authorities in the news-item is, therefore, not correct. The total value of import of marbles in the two ports for the period 1992-1995 (upto 31.3.95) is only Rs. 14 crores approximately. Hence, the allegation of a Rs. 100 crore fraud is also not correct.

विदेशी बैंकों से ऋण

*32. श्री दिग्विजय सिंह:
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पर विदेशी बैंकों जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक इत्यादि का कुल कितना ऋण है और कुल ऋण पर प्रति वर्ष ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इन बैंकों से वर्ष 1995-96 के लिए धन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है; यदि हां, तो किन-किन कार्यों की पूर्ति के उद्देश्य से और कितनी राशि की प्राप्ति के लिए आग्रह किया है;

(ग) क्या इन बैंकों ने भारत को 1995-96 के लिए दी जाने वाली कर्ज की राशि तय कर दी है; यदि हां, तो तय राशि कितनी है तथा यह राशि किस ब्याज दर पर और कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(घ) इन बैंकों से ली जाने वाली कर्ज की राशि के भुगतान के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) मार्च, 1995 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं यथा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और आईएफएडी को देय सरकारी खाते पर कुल बकाया विदेशी ऋण 81407.37 करोड़ रुपये था। इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भुगतान की गई ब्याज की राशि 1993-94 में 2511.86 करोड़ रुपये और 1994-95 में 2657.62 करोड़ रु० थी।

(ख) और (ग) यह भारत सरकार की प्रक्रिया नहीं रही है कि वह वार्षिक सहायता की आवश्यकता के यथार्थ आंकडों के संदर्भ में विशेष निवेदन करे। वर्ष 1995-96 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बैंकों/बहुपक्षीय एजेन्सियों जिसमें विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि शामिल हैं, ने 4.3 बिलियन अमरीकी डालर की राशि की वचनबद्धता की है। परियोजनाओं, राशि और ब्याज की दर आदि के संबंध में विशेष ब्यौरा दाता एजेन्सियों के साथ सहायता संबंधी बातचीत/करारों पर अंतिम निर्णय हो जाने के पश्चात् ही पता चलेगा।

(घ) ऋणों की वापसी अदायगी दाताओं के साथ परस्पर सहमति से संबंधित ऋण करारों की शर्तों के अनुसार तभी की जाएगी जब वे देय होंगे।

Irregularities in the telecast by DD-CNN.

*33. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the very first telecast after signing of Doordarshan agreement with CNN has tried to denigrate India by highlighting the cattle roaming in the streets;

(b) whether a high official of the CNN said it was a mere "teaser"; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) The 10 second promotional headline which related to a report on the buoyant state of the Indian economy shown on the DD/CNN channel on 30th June, 1995 had, inter-alia, contained shots of cattle on the streets of Bombay.

(b) Yes, Sir.

(c) The agreement has evoked both positive and negative reactions. Government, however, does not share the view that the agreement is against our national interests.

Advantages of Doordarshan CNN Agreement

*34. SHRI ANATRAY DEV-SHANKER DAVE: SHRI CHIMANBHAI MEHATA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what are the advantages and disadvantages of the agreement signed between CNN and Doordarshan;

(b) whether it would be possible for the CNN to broadcast news and events in an independent and objective manner through Doordarshan channel; and

(c) what is the expected revenue from the advertisement that may accrue after the release of CNN programmes on Doordarshan channel?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) The agreement will strengthen the Doordarshan platform.